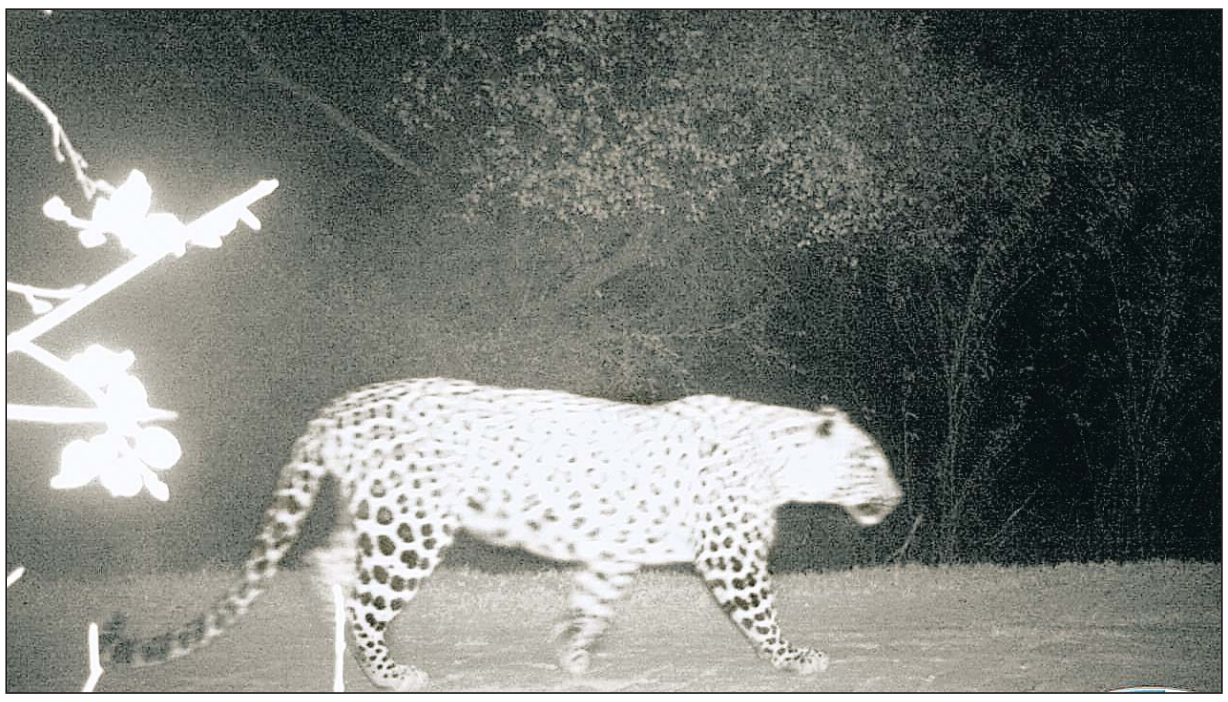

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक वर्ष बाद पैंथर का मूवमैंट दिखाई दिया।

ई.आर.सी.पी. की जानकारी पहले सदन में नहीं देने पर कांग्रेस ने हंगामा किया

■ आधा घंटा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई। अध्यक्ष देवनानी ने कल आधे घंटे की चर्चा कराने की घोषणा की।

जयपुर, 29 जनवरी (वि.सं.)। ई.आर.सी.पी. पर एम.ओ.यू. के मामले में सरकार से जवाब की मांग करते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा और नारेबाजी की। ई.आर.सी.पी. के मुद्दे पर पहले सरकार ने सदन को जानकारी नहीं दी। कांग्रेस ने इसी पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया। इसके बाद स्पीकर को 1 बजकर 4 मिनट पर आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। भाजपा विधायक जसवंत यादव ने कहा डेढ़ माह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फैसला करवा लाए।

आप लोग ताली तो बजा दो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन को अवगत कराते हुए कहा कि मंगलवार को शून्यकाल में ई.आर.सी.पी. मुद्दे को लेकर आधे घंटे की चर्चा की जाएगी।

शून्यकाल की कार्यवाही खत्म होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ई.आर.सी.पी. पर सदन के बाहर फैसला करने को लेकर मुद्दा उठाया। जूली ने कहा कि सदन चल रहा है, सदन के प्रति पूरे मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ऐसे समय ई.आर.सी.पी. योजना का एम.ओ.यू. किया है, लेकिन सदन को अवगत नहीं करवाया गया। इस पर स्पीकर ने जब उन्हें आगे बोलने की अनुमति नहीं दी तो नाराज कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी।

कांग्रेस नेताओं का कहना था कि, यह परम्परा रही है कि विधानसभा सत्र चल रहा हो तो कोई भी बड़े फैसला करने पर सबसे पहले उसकी सदन में जानकारी दी जाती है। सदन से पहले बाहर उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। ई.आर.सी.पी. के मुद्दे पर पहले सरकार ने सदन को जानकारी नहीं दी। कांग्रेस ने इसी पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया।

सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद शुरू हुआ। भाजपा विधायक जसवंत यादव ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लेकर कहा कि आपको कम उम्र में नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बार-बार वैल में आ जाए। यहां सब रिकॉर्ड होता है। ऐसे ही करते रहोगे तो थोड़े दिनों में नौटंकी का मैसेज चला जाएगा।

ई.डी.: लालू से 10 घंटे पूछताछ, कल तेजस्वी आयेंगे

पटना, 29 जनवरी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौकरी के बदले जमीन मामले में करीब दस घंटे पूछताछ की।

ईडी के समन के बाद लालू यादव पूर्वाह्न 11 बजे पटना स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी और राजद की राज्यसभा सदस्य मीसा भारती भी थीं, लेकिन उन्हें ईडी कार्यालय परिसर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। वह ईडी कार्यालय के बाहर ही डटी रहीं। लालू यादव करीब 9 बजे पूछताछ खत्म होने के बाद ईडी कार्यालय से बाहर निकले तब उनके समर्थकों ने उनके पक्ष में खूब नारे लगाए।

■ यह जांच 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री काल में नौकरी के बदले जमीन मामले में चल रही है।

इससे पहले भी जब ईडी कार्यालय में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही थी, तब बाहर यादव के समर्थक उनके पक्ष में नारे लगा रहे थे। यादव की बेटी मीसा भारती ने नारे लगा रहे लोगों से शांत रहने की अपील भी की, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर लालू समर्थकों पर नहीं हुआ।

सूत्रों के अनुसार, ईडी ने लालू यादव से नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में करीब 50 सवाल पूछे, जिसमें से अधिकांश का जवाब यादव ने हां और ना में ही दिया। कल इसी मामले में लालू यादव के पुत्र और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से भी पूछताछ होनी है।

नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मामले की जांच ईडी कर रही है। आरोप के अनुसार, यादव ने वर्ष 2004 से 2009 तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील सरकार के शासनकाल के दौरान रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी श्रेणी में उम्मीदवारों को दी गई नौकरियों के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूखंडों का निबंधन कराया था।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में दिखा पैंथर

■ एक साल पहले भी यहां काफी दिन पैंथर का मूवमैंट देखा गया था।

भरतपुर, 29 जनवरी (निसं)। विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में करीब एक वर्ष बाद फिर से पैंथर का मूवमैंट दिखाई दिया है। पैंथर दिखने की सूचना पर वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक साल पहले भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में काफी दिनों तक पैंथर का मूवमैंट देखा गया था।

डी.एफ.ओ. मानस सिंह ने पार्क में लगे कैमरा ट्रैप में पैंथरों की तस्वीर कैद होने के बाद एल ब्लॉक में पैंथर के मूवमैंट की पुष्टि की है। मॉनिटरिंग के लिए कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। स्टाफ को गश्त बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। आस-पास के गांव के लोगों को भी पैंथर के मूवमैंट के बारे में निर्देश दिए गए हैं। स्टाफ एवं पर्यटकों को एल ब्लॉक में नहीं जाने के लिए निर्देशित किया गया है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि, बयाना के बंध बरैठा एवं करौली के नव क्षेत्र से भोजन की तलाश में एवं नई टैरिटरी बनाने की तलाश में पैंथरों का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पंहुचना शुरू हुआ है।

संसद में सर्वदलीय बैठक आज

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स की मंगलवार को संसद अधिवेशन की पूर्व संध्या पर बैठक आयोजित की है।

संसद सत्र 31 जनवरी से प्रारम्भ होकर 9 फरवरी तक चलेगा।

सर्वदलीय बैठक संसद लायब्रेरी भवन में 30 जनवरी को प्रात: 11:30 बजे होगी।

संसद सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरु होगा और सरकारी संसदीय कार्यों की आवश्यकता के अनुरुप 19 फरवरी को समाप्त हो सकता है। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम केन्द्रीय बजट पेश करेंगी।

अप्रेल-मई में किसी समय होने वाले आम चुनाव से पहले संसद का यह अंतिम सत्र है।

'हमारी ममता बनर्जी से समझौते की भावना से बातचीत जारी है'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

■ कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बिहार के नेतागण, अखिलेश प्रसाद सिंह, शकील खान तथा डॉ. मोहम्मद जावेद के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि, नीतीश कुमार का प्रभाव एक राज्य (बिहार) तक सीमित है, पर इण्डिया गठबंधन सभी राज्यों में भाजपा के खिलाफ संघर्ष करेगा चुनाव में।

नई दिल्ली, 29 जनवरी। कांग्रेस महासचिव (कम्युनिकेशन्स) जयराम रमेश ने सोमवार को दावा किया कि, उनकी पार्टी की तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के साथ वार्ता जारी है तथा दोनों ही पार्टियाँ एक-दूसरे को सहयोग करने की नीति पर चलेंगी।

जयराम रमेश, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश करने के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह, शकील खान और डॉ. मोहम्मद जावेद के साथ मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि, नीतीश कुमार ने "इण्डिया" ग्रुप को त्याग दिया है, पर इसका प्रभाव केवल एक बिहार राज्य में है, जबकि अन्य राज्यों में सहयोगी दल भाजपा का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी की बदला लेने की राजनीति के तहत मोदी सरकार "इण्डिया" गठबंधन के नेताओं को तंग करने के लिए सी.बी.आई. और एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, गठबंधन अपनी लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि, झारखंड के मुख्यमंत्री को ये एजेसिंयां बदले की भावना के तहत ही परेशान कर रही हैं।

उन्होंने चुनाव आयोग का भी उल्लेख करते हुए कहा कि, वे चार माह से गठबंधन से मुलाकात करने से इंकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, वे (खड़गे) मतदान में ई.वी.एम. के उपयोग का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि, चुनाव परिणामों के लिये वी.वी.पी.ए.टी. काम में लिया लाये।

सिमी पर प्रतिबंध 5 वर्ष बढ़ा

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे पांच वर्ष के लिए 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित कर दिया है।

गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि, (सिमी) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत पांच साल की अवधि के लिए विधिविरूद्ध संगठन घोषित कर दिया है। सिमी पर इससे पहले पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी 2019 को लगाया गया था। बयान में कहा गया है कि, सिमी, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा है जो देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।

सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

डिस्कॉम का ए.ई.एन. 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

■ विद्युत पोल लगाने का बिल पास करने के लिये यह रकम मांगी गयी थी।

डूंगरपुर, 29 जनवरी (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई ने सोमवार को डूंगरपुर में कार्यवाही करते हुए, राजेन्द्र कुमार सांवरिया, सहायक अभियंता (प.व.स.) साबला, अजमेर डिस्कॉम, जिला डूंगरपुर, को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि, ब्यूरो की उदयपुर इकाई को परिवादी ने शिकायत की थी कि, उसकी फर्म ने जीएसएस साबला क्षेत्र में विद्युत पोल लगाने के जो कार्य किए थे उनके बिल पास करने की एवज में राजेन्द्र कुमार सांवरिया, सहायक अभियंता (प.व.स.) साबला, अजमेर डिस्कॉम, जिला डूंगरपुर, 85 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा है। जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस, राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरविज़न में ब्यूरो की उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रमसिंह राठौड़ के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करके सोमवार को पुलिस निरीक्षक डॉ.सोनू शेखावत ने मय टीम डूंगरपुर में ट्रैप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र कुमार सांवरिया पुत्र परमानन्द सांवरिया को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार कर लिया है।

ब्यूरो के उप-महानिरीक्षक पुलिस राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है।

तथा इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

केन्द्र व राज्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि श्रीगणपति ट्ययूबवेल और श्रीश्याम कृपा ट्ययूबवेल कम्पनी ने भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी पूर्णता प्रमाण पत्र पेश कर जल जीवन मिशन में करीब 900 करोड रुपए के टेंडर का भुगतान ले लिया। बाद में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इस पर इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी गई, लेकिन राज्य सरकार ने मामले में कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता संस्था की ओर से पुलिस और एसीबी को कई बार लिखित में शिकायत कर कार्रवाई का आग्रह किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने 3 सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा बम के आरोपी सरवर की जमानत बरकरार रखी

■ राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दी गयी जमानत के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की थी, जिसे सुनवायी के बाद खारिज कर दिया गया।

जयपुर, 29 जनवरी (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई, 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बीच जिंदा बम मिलने से जुडे मामले में आरोपी सरवर आजमी को मिली जमानत को बरकरार रखा है।

इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की एसएलपी पर दिए।

राज्य सरकार ने एसएलपी में हाईकोर्ट के अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपी को इस आधार पर जिंदा बम मामले में जमानत दी थी कि वह जयपुर बम ब्लास्ट के मुख्य मामले में दोषमुक्त हो चुका है। जबकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के जरिए चुनौती दे रखी है और यह याचिका अभी लंबित चल रही है। जिंदा बम मामले में भी सरवर आजमी प्रथम दृष्टया आरोपी है और इस केस की ट्रायल चल रही है। इसके अलावा आरोपी सरवर आजमी देशभर में अन्य जगहों पर हुए बम ब्लास्ट केस में भी आरोपी है। इसलिए आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार करते हुए एसएलपी खारिज कर दी। दरअसल हाईकोर्ट में आरोपी सरवर आजमी की ओर से कहा था कि वह जयपुर बम ब्लास्ट केस में दोषमुक्त हो चुका है। जिंदा बम मामले की ट्रायल चल रही है। वह 2009 से ही जेल में बंद है तथा बम धमाके व जिंदा बम के ज्यादातर गवाह व दस्तावेज भी समान हैं। ऐसे में उसे भी जमानत दी जाए।

हेमन्त सोरेन 31 को ई.डी. को जानकारी देंगे

■ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने कहा कि, ई.डी. ने 31 तक जानकारी मांगी थी तथा वह उन्हें उपलब्ध करा दी जायेगी।

रांची, 29 जनवरी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि, 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में होंगे और जिन जरूरी जानकारियों की आस में ईडी है, उसे उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे।

भट्टाचार्य ने आज यहां हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, 20 जनवरी को ईडी के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम कुछ जानकारियों के लिए मुख्यमंत्री आवास आयी थी। 17-18 सवाल मुख्यमंत्री से किए थे। तथाकथित विसंगतियों की ओर इशारा करते वे जानकारी मांग रहे थे।

हालांकि पूर्व में जो समन उन्हें जारी किया था, उसमें पी.एम.एल.ए. की धारा 50 के तहत यह नहीं आता। बड़गाईं जमीन के बारे में पूछा। इसका पता पूर्व में लगाया था तो यह बात सामने आयी थी कि यह तो भुईंहरी प्रवृत्ति की जमीन है, जिसकी खरीद बिक्री संभव नहीं। इस पूछताछ के बाद भी मुख्यमंत्री को 31 जनवरी तक कुछ बिंदुओं पर जानकारी के लिए ईडी की ओर से कहा गया। इसमें दिक्कत नहीं है। जो भी जानकारी चाहिये, दी जायेगी।

भट्टाचार्य के मुताबिक अभी मुख्यमंत्री निजी काम से दिल्ली गये हैं। वे वापस लौटेंगे जरूर। पिछली बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री ने 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में ईडी को एक बजे आने और जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही है।

भट्टाचार्य ने कहा कि, चुनाव आयोग के पास लोक प्रतिनिधियों से संबंधित सारी जानकारियां रहती हैं। पर ईडी उसे आधार नहीं बना रही।

उन्होंने कहा कि, सोहराय भवन, रांची के अलावा 2018-2022 की अवधि में हुए ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी मांगा गया था। यह भवन मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी के नाम पर है। जब कहीं से कोई चीज नहीं बनी तो राजनीतिक इशारे पर मुख्यमंत्री को परेशान करने का खेल चल रहा। सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कुछ जरूरी असाइनमेंट को छोड़ 1-3 माह तक का पूर्व से तय रहता है। भट्टाचार्य कहा कि, नौ फरवरी से वित्तीय वर्ष 2024-25 का विधानसभा का बजट सत्र तय है। अभी ऐसे में ईडी के स्तर से पूछताछ के लिए इस तरह से किया जाना गैर वाजिब है। दूसरा संवैधानिक प्रक्रियाओं के निर्वहन में भी इससे सरकार को दिक्कत होती है।

नीतीश की पांचवी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उम्मीदवार बताते हुए कहा कि, "यदि आप सभी विलय और अधिग्रहण के बावजूद, नौ बार, सी.ई.ओ. चुने जाते हैं तो आप "कॉर्पोरेट भारत" के सी.ई.ओ. के लिए एक आदर्श उम्मीदवार हैं।

एक अन्य "एक्स" उपयोगकर्ता ने, कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के एक दृश्य के साथ लिखा कि, "वो शपथ क्यों पढ़ रहे हैं, अब तक तो उनको मुंह-जुबानी याद हो गयी होगी।"

कांग्रेस नेता, जयराम रमेश ने भी निशाना साधते हुए कहा कि, "शपथ लेने के बाद, नीतीश कुमार जी, अपना मफलर राजभवन में भूल गए थे और आधे रास्ते से जब वो राजभवन वापस पहुंचे मफलर लेने तो राज्यपाल भी हैरान हो गए कि, इस बार तो पंद्रह मिनट भी नहीं बीते हैं।"

नीतीश की एक तस्वीर का शीर्षक पल्टी पुत्र था, जो कि, प्राचीन शहर, पाटली पुत्र के नाम को बदल कर बनाया गया है।

अन्य संदेशों में उन्हें मज़ाक में, "बिहार के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री" कहा गया है। एक "एक्स" उपयोगकर्ता ने कहा कि, "सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने सभी यू-टर्न संकेतों को हटाने और उनकी जगह नीतीश कुमार की तस्वीर लगाने की घोषणा की है।"

'यह कोई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तरह उल्लेख कैसे कर सकते हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? आप ने बस खड़े होकर उल्लेख कर दिया। हम लागत (कॉस्ट) लगाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को देय होगी।"

वकील ने कहा कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है।

इस पर बैंच ने कहा, "तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट में आप सिर्फ खड़े हो जाते हैं और याचिका का उल्लेख कर देते हैं।" अंतत: कोर्ट ने वकील से कहा कि, वे किसी वरिष्ठ वकील से इस बात पर चर्चा करें कि, शीर्ष अदालत के समक्ष मामलों का उल्लेख कैसे किया जाता है।

नीतीश प्रकरण पर राहुल की चुप्पी

किशनगंज, 29 जनवरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने पर चुप्पी साधे रखी वहीं उत्पीड़ित एवं वंचित लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने की मांग की।

गांधी ने अपनी "भारत जोड़ो न्याय यात्रा" के दौरान बिहार के किशनगंज जिले में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि, राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना आवश्यक है और उत्पीड़ित एवं वंचित लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसे जरूर कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि,

■ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरे देश में जाति जनगणना की मांग की है।

उनकी पार्टी हमेशा शोषितों और वंचितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है।

कांग्रेस नेता ने अपने संबोधन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने और बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हाथ मिलाने जैसे नाटकीय घटनाक्रम पर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कहा कि, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) देश में नफरत फैला रहे हैं, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है। वहीं, उनकी पार्टी समाज के सभी वर्गों के बीच प्रेम, भाईचारे और स्नेह बनाये रखने में दृढ़ता से विश्वास करती है।

अंतरिम बजट अधिकतर सरकार की आमदनी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ जैसा कि, ए.आई. विशेषज्ञ कह रहे हैं, अब ए.आई. का विकास "प्राइवेट पार्टिसिपेशन" पर निर्भर करेगा, अतः स्टार्टअप को भारी प्रोत्साहन देना होगा। जैसा कि, अब तक का अनुभव है, "स्टार्टअप" काफी बड़ी संख्या में फेल होते हैं। इस फेलियर को "एब्ज़ॉर्ब" करने के लिये बड़ी रकम चाहिये सरकार को।

■ साथ ही, जैसा कि कोविड की महामारी ने सिखा दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन महामारियों का दौर हर दो-तीन साल में आएगा। इन माहमारियों से जूझने के लिये रकम चाहिये, जिसका प्रावधान बजट में रखना होगा।

था। ये उनके पीड़ा भरे बजट भाषणों में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होता था।

सौभाग्य से, वर्ष 1992-93 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत और उसके बाद के बजट, देश की महत्वाकांक्षाओं का कथन बन गए हैं। पूर्व वित्त सचिव और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, बिमल जालान ने एक बार कहा था कि, "अब हम बड़े लक्ष्य रख सकते हैं।"

आम चुनावों को देखते हुए, बजट का सबसे महत्वपूर्ण अंश किसान के मन को जीतना होगा। किसान-वर्ग और उनकी सहानुभूति, आम चुनावों में बहुत महत्व रखती है। देश की कृषि अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों में सुधार करने के सरकारी प्रयासों का प्रतिकूल परिणाम रहा था। किसान वर्ग को वर्तमान मंडी व्यवस्था में बदलाव और अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना पसंद नहीं आई। अन्ततः सुधारों को वापस लेना पड़ा। किसानों का विश्वास कैसे जीता जाये और इसके लिए कुछ किसानों की पसन्द की योजनायें बनाने में वित्त मंत्री की असली परीक्षा होगी।

जो भी वर्तमान विश्व को समझता है वह "ऑटिफिशियल इन्टेलीजैन्स" के विचार से बच नहीं सकता। इसे लोग ए.आई. के नाम से अधिक जानते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान अति उत्साह में, इसकी व्याख्या अमेरिका और भारत के मध्य सहयोग के रूप में की थी। लेकिन ए.आई. अब इससे कही अधिक बड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद इस क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग कुछ पिछड़ सा गया है।

यह हमें संबंधित क्षेत्र में ले जाता है, "स्टार्टअप्स" को बढ़ावा देना। यह वस्तुतः आर्थिक रोमांस की कहानियां ही हैं जिसमें रचनात्मक युवाओं (पुरुषों एवं महिलाओं) के छोटे समूहों द्वारा व्यवसाय और उत्पादों में नवीन प्रयास किए जा रहे हैं। यह व्यवसाय के लिए नई रूपरेखा देने वाले व्यक्ति या सहयोगियों की बौद्धिक पूंजी है।

भारतीय बजट को "स्टार्ट अप्स" को विकसित करने के लिए, आवश्यक इको-सिस्टम प्रदान करना होगा। इन स्टार्ट अप के लिए, आसान फंड आसान नियम और मंजूरी व्यवस्था तथा व्यवसाय करने के लिए लचीले ढाँचे की आवश्यकता होगी। वास्तविक आय निर्धारण के लिए, कर लाभ प्रदान करना और स्टार्टअप अनुकूल कर ढाँचा, समय की आवश्यकता है। यथार्थ में, कुल मुट्ठी भर ही स्टार्टअप ही सफल होंगे और चलते रहेंगे। असफल स्टार्टअप के परिसमापन के लिए एक बहुत समझदार और आरामदायक रूपरेखा की आवश्यकता होगी।

महामारी ने हमें दर्दनाक सबक सिखाया है और हमें अगली संभावित महामारी का सामना, सफलता से कर सकने के लिए तैयार रहने की पहल करनी चाहिए। "हैल्थ केयर सिस्टम" को प्राथमिकता एवं निवेश मिलना चाहिए। निजी पहल हुई हैं, लेकिन सरकार ढाँचे कमज़ोर और अपर्याप्त हैं। इनमें बड़े निवेश की आवश्यकता है। आगामी बजटों में भारत के बुनियादी स्वास्थ्य ढाँचे को विकसित करने का प्रयास होना चाहिए।

भारतीय बजट में इन समस्याओं के उपायों का प्रावधान होना चाहिए। बेशक, इसमें धन लगेगा लेकिन अब हम स्वास्थ्य में अधिक निवेश वहन कर सकते हैं।

नि:संदेह, वृहद आर्थिक और राजकोषीय स्थिति सुखद है। औसत अप्रत्यक्ष कर संग्रह, मुख्यत: जी.एस.टी., अतीत की विकट भविष्यवाणियों से कहीं अधिक है। वर्तमान में यह डेढ़ लाख करोड़ प्रतिमाह से अधिक है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल है जो औद्योगिक और सेवा अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्शाता है। राजकोषीय घाटा, सीमा में रहने की संभावना है।

कोटा में एक और छात्रा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सूचना पर बोरखेड़ा थाना पुलिस एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में पहुंची। वहां पुलिस ने परिजनों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। बोरखेड़ा थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि घटना सोमवार सुबह की है। मृतका 18 वर्षीय छात्रा निहारिका सिंह है। परिजनों के अनुसार वह जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन की तैयारी कर रही थी। वह कई दिनों से तनाव में थी। एएसआई उदय सिंह का कहना है कि परिजनों से भी जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि, बाद में पुलिस को एक नोट मिला जिसमें कारणों का जिक्र किया गया है।

फिलहाल पुलिस इस संबंध में गहन पड़ताल कर रही है। मृतका के चचेरे भाई विक्रम सिंह का कहना है कि निहारिका ऑनलाइन कोचिंग कर रही थी। बीते साल भी उसने 12वीं की परीक्षा दी थी जिसमें कम प्रतिशत से पास हुई थी। इसीलिए वह दोबारा 12वीं की तैयारी कर रही थी और इसी के साथ जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी।

उसका जेईई मेन का पेपर 30 या 31 जनवरी को था। इसी को लेकर वह लगातार तनाव में रहती थी। वह करीब 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर रही थी। मूलत: उसका परिवार झालावाड़ जिले के अकावद गांव निवासी है जबकि कोटा में उनका खुद का मकान है। पिता विजय सिंह बैंक में सिक्योरिटी गनमैन है। निहारिका तीन बहिनों में सबसे बड़ी थी। पढ़ाई में भी अच्छी थी।

डॉ. मनमोहन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होंगे। पचास राज्यसभा सदस्य 2 मार्च को तथा 6 सदस्य 3 मार्च को रिटायर होंगे।

दिल्ली के 3 राज्यसभा सदस्य पहले ही चुने जा चुके हैं, सभी तीन सीटें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को गईं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908